

संपादकीय

भारतीय टीके पर फिजूल सवाल

कोरोना रोधी टीकों के खिलाफ जब अफवाहों का बाजार गरम हो, तब सकी प्रभावशीलता पर बार-बार उत्तर सवाल लोगों की उलझन और दंडा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस मसले को तत्परता के साथ उलझाया जा रहा है, और जल्द ही सुखद नतीजे मिलने की उम्मीद है। नेविशील्ड फिलहाल इसी दुश्क्र में उलझ गया है। यूरोपीय संघ के देशों स आधार पर कोविशील्ड से मिलने वाली सुरक्षा को सदिक्ष बता रहे हैं एक चंद लोगों में इसके दुष्परिणाम, यानी साइड इफेक्ट दिखे हैं। जबकि से मूलत-बिटिश संस्थान ऑक्सफोर्ड/एस्ट्रोजेनेका ने ही ऐयार किया है, जिसका उत्पादन भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। सबसे अहम सवाल यह है कि पहले जिस टीके को यूरोपीय देशों अपने यहाँ इस्तेमाल की अनुमति दी और उसका व्यापक प्रचार-प्रसार की गयी किया, अब उससे मिलने वाली सुरक्षा पर वे बत्तों सवाल खड़े कर रहे हैं? इसकी कई वजहें हो सकती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कसी भी टीके को पर्याप्त परीक्षण के बाद ही बाजार में उतारा जाता है। परीक्षण पहले जानवरों पर होते हैं, उसके बाद मानवों पर किए जाते हैं। इसानों में भी पहले चुनिंदा लोगों को टीका लगाया जाता है, और उसके नतीजों के आधार पर जन-समुदाय के लिए उसे सुरक्षित घोषित किया जाता है। चूंकि कोविड-19 की मारकता अधिक थी और इसीमारी से दुनिया भर में लाखों लोगों की जान जा रही थी, इसलिए गोरोना रोधी तमाम टीकों के कमोबेश आपात इस्तेमाल की अनुमति दी गई, जिसका मतलब था कि इनका पूरा परीक्षण तो नहीं हो सका है, लेकिन न्यूनतम सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखा गया है और उनमें टीके के प्रुक्षित पाए गए हैं। अब चूंकि व्यापक स्तर पर टीकों का इस्तेमाल हो रहा है और करोड़ों लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं, तो उसमें व्यापरिणाम के चंद मामले कोविशील्ड के खिलाफ जा रहे हैं व प्रश्न ठाए जा रहे हैं।

पर क्या इन सवालों को इतनी अहमियत देनी चाहिए? शरीर के भीतर गहर से डाली जाने वाली कोई भी चीज का अपना साइड इफेक्ट होता है। टीके का भी यही गणित है। हालांकि, इसमें भी कुछ दुष्परिणाम टीके की बजह से दिखते हैं, तो कुछ मनोवैज्ञानिक कारणों से। मसलन, टीका उपर्युक्त गते ही कंपकंपी आना अथवा बेहोश होने की घटनाएं आमतौर पर दमागी रूप से भयभीत होने के कारण घटती हैं, जबकि बुखार आना, चमत्कारी आना या फिर चक्कर आदि समस्याएं टीके के कारण हो सकती हैं। शुरू-शुरू में कोरोना रोधी टीकों को लेकर ये आशंकाएं कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि व्यापक स्तर पर इनका परीक्षण नहीं हो सका था। इन टीकों में संदर्भ में यह अध्ययन भी नहीं हो सका था कि वायरस के खिलाफ किस हद तक कारगर हैं? जिन लोगों को टीके लगे, क्या उन्हें भी वायरस ने अपना शिकार बनाया? और अगर वे बीमार पढ़े, तो बीमारी ने गंभीरता कितनी रही? ये कुछ ऐसे सवाल थे, जिनके जवाब बाद में लाशे गए। कुछ सवालों के उत्तर तो अब भी खोजे जा रहे हैं। अभी तक के तमाम अध्ययन यही बता रहे हैं कि जिन टीकों को अनुमति दिली है, वे सभी वायरस के खिलाफ काम कर रहे हैं, और कोरोना से बचा रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों को टीके लगे, और वे यदि बीमार भी हुए, तो उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और जल्दी ठीक हो गए। अत्यं दर भी टीके लगे व्यक्तियों में बहत कम दिखती।

तु दर मा टाक लग व्याकवा म बहुत कम दिखा। समस्या सिर्फ यह है कि कोविशील्ड टीका लगाने के बाद कुछ लोगों खून के थके जमने की शिकायतें आई हैं। यूरोपीय देशों में इसके नारण कुछ मौतें भी हुई हैं। नतीजतन, उसके खिलाफ माहौल बनता गला गया। असल में, टीकाकरण के बाद मौत को मामूली मसला नहीं जाता। अपने यहां भी गर्भाशय कैंसर की एक वैक्सीन इसलिए तिब्बधित कर दी गई थी, क्योंकि टीका लगाने के बाद दक्षिण में एक हिला ने दम तोड़ दिया था, जबकि उस टीके को आज भी कई स्त्री रोग व्यवेषज्ञ व डॉक्टर काफी सफल बताते हैं और बच्चों को लगाने की पफारिश करते हैं।

सफारिश करत है। देखा जाए, तो कोई भी टीका शत-प्रतिशत सुरक्षित नहीं होता। मगर कोरोना रोधी टीके के साथ अच्छी बात यह है कि वायरस के खिलाफ ये नागरग सांबित हुए हैं। अपने यहाँ इस्तेमाल हो रहे कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों टीकों के अच्छे फायदे दिखे हैं। लिहाजा, टीका 'भावशाली' हो, और व्यापक तौर पर उसके लाभ दिख रहे हों, तो व्यूरिणम की एकाध घटनाओं को हमें अभी नजरंदाज कर देना चाहिए। नागर बहुत कम संसाधन में अपने नागरिकों को कोरोना से बचाने का निभयन चला रहा है। इसे पटरी से उत्तरने नहीं देना चाहिए। सार्वजनिक वास्थ्य का यही तकाजा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता बेशक एकाध ग्रामतों को भी तबज्जों दें (जिसे मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि हरेक नागरिक को उसका अधिकार मिलना ही चाहिए), तेकिन व्यापक हित में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हर नागरिक के लिए टीके की वकालत नहरते हैं। बात जब जान से जुड़ी हो, तो हक का सवाल स्वाभाविक तौर पर पीछे छूट जाता है। साफ है, कोविशील्ड को लेकर चल रहा विवाद अभी कोई अर्थ नहीं रखता। इसको लेकर ज्यादा खौफ खाने की जरूरत नहीं है। सरकारों को भी आम लोगों में पनप रही चिंता को खत्म करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए। लोगों को यह समझाना होगा कि टीके की प्रभावशीलता को महत्व दें। तथ्य यही है कि कोरोना से अंत्रमित होने के बाद महज एक फीसदी लोगों में मृत्यु का खतरा होता है, जबकि टीकाकरण के बाद मौत का यह खतरा घटकर 0.0001 प्रतिशत हो जाता है। इसीलिए टीकों से मिलने वाली सुरक्षा के आधार पर भी लोगों को अपना मत बनाना चाहिए। जोखिम और खतरे जीवन के हर गोड पर आते रहते हैं, लेकिन जिन उपायों से ये खतरे कम हो सकें, उन्हें नस्रुर अपनाना चाहिए। कोरोना रोधी टीके भी हमें ऐसे ही जोखिम से बचाते हैं।

प्रवाण कुमार सह

कार्यपालिका और विधायिका की जवाबदेही तय है, लेकिन न्यायपालिका किसी संस्था के प्रति जवाबदेह नहीं

लोकतंत्र भारत की जीवनशैली है। सर्विधान की उद्देशिका में राष्ट्र राज्य की शक्ति का मूल स्रोत 'हम भारत के लोग हैं'। उद्देशिका में भारत के लोगों की सर्वोच्च प्रभुता की घोषणा है। भारत के लोगों ने प्रभुत्व संपन्न सर्विधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से देश का सर्विधान बनाया था। भारत के लोग अपनी प्रभुता का प्रयोग केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल के माध्यम से करते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। सर्विधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। इसे संसद या विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधि की सर्वेधानिकता जांचने के अधिकार भी हैं। तीनों संस्थाएं सर्विधान से शक्ति पाती हैं। चुनाव के माध्यम से नागरिक अपने मन की सरकार चुनते हैं। चुनाव सर्वेधानिक जनतंत्र का महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन गत सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने एक कार्यक्रम में कहा, 'चुनाव से सत्ता में आए लोगों को बदलने का अधिकार निरंकुश शासन से बचे रहने की गारंटी नहीं है।' उहोंने राजनीतिक आलोचना और विपक्ष की विवादों के बारे में ऐसा कहा है।

की आवाज को आदर्श लोकतंत्र प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। यहां तक सब ठीक है, लेकिन उनके वक्तव्य में न्यायपालिका के कामकाज पर कोई सारावान् चर्चा नहीं है।
 प्रधान न्यायाधीश ने तर्कसंगत के साथ अतकसंगत विचारों को भी सम्मान देने की अपील की है। इसीलिए उनका ताजा वक्तव्य विश्लेषण योग्य हो गया है। उन्होंने न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही है। साथ ही स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को

6 6 6

विधायिका या कार्यपालिका द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्यन्त्रित नहीं किया जा सकता। इससे विधि चाहिए? विधायन संसद और विधानमंडल का अधिकार है। किसान आंदोलन

A white cylindrical storage tank with a brownish-red top cap, set against a clear blue sky. The tank is positioned at the bottom of the frame, with its top reaching towards the center.



उपबंध है। प्रश्नगत निरहता की सुनवाई का कार्य संविधान ने लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के

सभापति, विधानसभा,
विधान परिषद् के

अस्मिता के प्रति आदर भी होना चाहिए। यह सब संपूर्ण समाज में होना चाहिए। यह होने पर ही वास्तव में लोकतांत्रिक समाज की प्राप्ति संभव है।' कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अपने कार्यक्षेत्र में रहना चाहिए। कुछ समय पहले कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण की सुनवाई के दौरान विशेष प्रकार की गाड़ियों के प्रवेश पर लेकी लगाने के निर्देश दिए थे। कर लगाना न्यायपालिका का क्षेत्र नहीं है। बंगल चुनाव के बाद भारी हिंसा हुई। न्यायिक सुनवाई में लोगों की उम्मीदें थीं। विषय महत्वपूर्ण था, लेकिन दो न्यायमूर्तियों ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया। इसका औचित्य समझ में नहीं आता। मुख्य न्यायाधीश ने वास्तविक लोकतंत्र के विकास के लिए बेशक अच्छी बातें की हैं, लेकिन न्यायपालिका में जरूरी सुधार की आवश्यकता यक्ष प्रश्न है।

उन्होंने इंटरनेट मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर भी टिप्पणी की है। कहा है कि 'नए मीडिया टूल में किसी भी बात को बढ़ा-चढ़ाकर बताने की क्षमता है। वे सही-गलत, अच्छे-बुरे और असली-नकली के बीच फर्क करने में असमर्थ हैं।' उन्होंने ठीक कहा है कि मीडिया द्वायल मामलों के विचारण में मार्गदर्शक नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी कहा कि 'न्यायाधीशों को कभी भी भावुक राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए।' उन्होंने कोरोना महामारी पर भी विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि 'हमें आवश्यक रूप से खुद से पूछना होगा कि हमने अपने लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए कानून के शासन का किस हद तक इस्तेमाल किया।' ऐसा आत्मचित्तन समय की मांग भी ही।

मध्य प्रदेश में स्कूल फीस की वृद्धि पर तकरार, उलझन में शिवराज सरकार

हाल ही में निति आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए स्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के संसंदर्भ में भारत के 36 राज्यों एवं केंद्रायासित प्रदेशों की कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार जहां समस्त भारत के स्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कुल अंक 2019 में 60 से बढ़कर 2020 में 66 तक पहुंच गए हैं, वहीं सभी राज्यों में यह बढ़िया कम या ज्यादा देखने को मिलता है। एसडीजी के संसंदर्भ में शीर्ष पर 75 अंकों के साथ केरल है, जबकि सबसे नीचे 52 अंकों के साथ बिहार है। बिहार इन दो वर्षों में 48 से 52 अंकों तक ही पहुंचा, जबकि असम 49 से बढ़कर 57 अंकों तक पहुंचा। नीचे के पायदान के अन्य राज्यों में झारखण्ड 50 अंकों से 56 अंक, मध्य प्रदेश 52 अंकों से 62 अंक, राजस्थान 50 अंकों से 60 अंक तक पहुंचे। बांगल भी 56 अंकों से बढ़कर 62 अंकों तक ही पहुंचा। उत्तर पूर्व राज्यों में मेघालय 52 अंकों से 62 अंकों तक पहुंचा, जबकि अरुणाचल प्रदेश 51 अंकों से 60 अंकों तक पहुंचा। वहीं नगालैंड 51 अंकों से 61 अंकों तक और मणिपुर 59 अंकों से 64 अंकों तक पहुंचा। हालांकि इस बीच कुछ राज्य आकांक्षा से निष्पादक की श्रेणी में आ गए और कुछ अन्य पिछले राज्यों का भी कार्य निष्पादन ठीक रहा है, लेकिन अभी भी उनका स्तर बेहतर राज्यों से काफी नीचे है। अभी भी सात राज्य 60 या उससे कम अंक ही प्राप्त कर पाए हैं। छह राज्यों के अंक 60 से अधिक लेकिन 65 से कम हैं। 65 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले राज्यों को फंट रनर (यानी अगड़े माना गया है)। अभी भी 13 राज्य ऐसे हैं, जिन्हें अगड़े की श्रेणी में आना बाकी है। प्रश्न यह है कि हमारे सभी राज्य

अगड़े की श्रेणी में कैसे आ सकते हैं। देखा जाए तो हमारा देश लंबे समय से क्षेत्रीय अर्थात् असमानताओं से जूझा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के फार्मूले के आधार पर विभिन्न देशों की रैकिंग उनके मानव विकास के स्तर के आधार पर की जाती है। एसडीजी में कई कारकों को शामिल किया गया है जो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं थे। मानव विकास सूचकांक में प्रतिव्यक्ति आय, स्वास्थ्य के स्तर और शिक्षा के स्तर को उनके संकेतकों के आधार पर शामिल किया गया था। वर्तमान में एसडीजी में 17 लक्ष्यों को शामिल किया गया है। इन लक्ष्यों में गरीबी उच्चलून, शून्य भुखमरी, अच्छा स्वास्थ्य, स्तरीय शिक्षा, लिंग समानता, स्वच्छ जल और सफाई, सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम और ग्रोथ, समानता, शांति और न्याय हेतु सबल संस्थाएं, जिम्मेदारी पूर्ण उपभोग एवं उत्पादन इत्यादि शामिल हैं। इन लक्ष्यों के कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए 117 संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश के पिछड़े राज्यों में अधिक जनसंख्या वाले राज्य बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा आदि शामिल थे। कई बार इन राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश) के नामों को जोड़कर 'बीमारू' राज्य भी कहा जाता रहा है। यदि इन 'बीमारू' राज्यों के पिछले तीन दशकों का आकलन करें तो वर्ष 1990-91 से 2004-05 के बीच बिहार की ग्रोथ रेट माइनस एक प्रतिशत, मध्य प्रदेश की 1.78 प्रतिशत, असम की 3.18 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश की 2.79 प्रतिशत ही रही। लेकिन राजस्थान की ग्रोथ 5.11 प्रतिशत और ओडिशा की 5.52 प्रतिशत रही। अगड़े राज्यों की ग्रोथ इस दौरान

6.03 प्रतिशत, जबकि पिछड़े राज्यों की मात्र 2.7 प्रतिशत ही रही। लेकिन 2004-05 से 2019-20 के दौरान पिछड़े राज्यों की ग्रोथ सम्पादनजनक रही। बिहार में जीडीपी ग्रोथ 8.6 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 7.9, उत्तर प्रदेश में 6.5, राजस्थान में 6.9, ओडिशा में 5.9 और झारखण्ड में 6.7 प्रतिशत की दर से दर्ज की गई। यह भी सच है कि चूंकि इन राज्यों में प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम है, इसलिए तेज आर्थिक संवृद्धि के बाद भी प्रतिव्यक्ति आय के दृष्टि से ये राज्य अभी भी बहुत पीछे हैं, जिस कारण वहाँ के लोगों में गरीबी, खूबसूरी अधिक है। एसडीजी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश दो ही बार में 42 अंकों से बढ़कर 60 तक पहुंचा। ऐसा इसलिए है कि यहाँ विद्युतीकरण शत प्रतिशत और एलपीजी कनेक्शन लगभग सभी परिवारों को दिया जा चुका है। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश के अंक 25 से बढ़कर 60 हो गए हैं। स्वच्छ जल एवं सफाई व्यवस्था में भी उत्तर प्रदेश के अंक दो वर्षों में 55 से 85 पहुंच गए हैं। शांति, न्याय और सबल संस्थाओं के संदर्भ में भी इस राज्य के अंक 61 से बढ़कर 79 तक पहुंच गए हैं। देखा जाए तो चाहे 17 कारकों में से उत्तर प्रदेश का कार्यनिष्ठादान सिर्फ पांच कारकों में ही उल्लेखनीय रूप से बेहतर हुआ है, लेकिन इन्हीं कारकों के कारण इस राज्य को संयुक्त अंकों 11 अंकों की बढ़त हासिल हुई है। यानी अन्य कारकों में भी यदि बेहतरी होती है तो उत्तर प्रदेश अगड़े राज्यों में आ सकत है। गौरतलब कि जैसे-जैसे प्रतिव्यक्ति आय बढ़ती है, सरकार का राजस्व भी बढ़ता है, जिसके चलते शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं में बेहतरी संभव है।

ग्रीस के जरिये भारत का भूमध्यसागरीय राजनय, दोनों देशों के बीच संबंधों की पृष्ठभूमि

भारत ने जिस तरह से क्षेत्रीय स्थिरता के लिए साइप्रस और लीबिया का उल्लेख करते हुए ग्रीस से चर्चा की और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मिलावतों की शुचिता बनाए रखने की बात की, उससे साफ है कि तुर्की को भी भारत एक

संदेश देना चाहता था। तुर्की की सरकार को डर है कि पूर्वी भूमध्यसागर का इस्तेमाल तुर्की को अलग-थलग करने की कोशिशों में किया जा रहा है। ग्रीस और साइप्रस ने यूरोपीय संघ से तुर्की की कार्रवाई के खिलाफ समर्थन की मांग की है और इनके साथ ही तुर्की के क्षेत्रीय विरोधी भी इस प्रदिप्ति में शामिल हो गए हैं।

A photograph showing two men in suits and face masks seated at a table, engaged in a meeting. The man on the left is Secretary of State Antony Blinken, and the man on the right is Greek Foreign Minister Nikos Dendias. They are positioned in front of flags, with the U.S. flag on the left and the Greek flag on the right.

वास्तक सीमा पार आतंकवाद के द्वारा नामने आए खतरों की गंभीरता पर ये देशों ने बात की और सहमत हुए कि इस संबंध में मिल-जुल कर कार्य करने की जरूरत है।
ग्रीस ने भारत की संयुक्त राष्ट्र में आयी सदस्यता का समर्थन किया और नाथ ही संयुक्त राष्ट्र की संचयन और कार्यों में अपेक्षित सुधारों के लिए भी अपनी मंशा जाहिर की। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आयी सदस्यता को पाने के लिए

पूर्व ही ग्रीस और उसके पड़ोसी तुर्की के बीच सागरीय क्षेत्र के स्थानित्य को लेकर विवाद हो गया था। तुर्की ने ग्रीस के अनन्य आधिक खेत पर अपना दावा कर दिया था और ग्रीस ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र सागरीय नियमों व कानूनों के तहत उस पर ग्रीस का ही अधिकार है। निश्चित रूप से भारत जिस प्रकार सभी देशों की सागरीय संप्रभुता और स्वायत्ता का समर्थन करता रहा है, ग्रीस भारत की उस उच्च कोटि की प्रतिबद्धता से परिचित रहा है। भारत ने अपने मजबूत सामरिक साझेदार ब्रिटेन की नाराजगी को न देखते हुए कुछ समय पहले चांगोस द्वीप पर मरीशस के जायज हक का समर्थन किया

था। ग्रीस के भी जायज सामग्रीय हक में भारत अपनी आवाज उठा सकता है, ऐसा ग्रीस को लगता है। नाटो सदस्य ग्रीस और तुर्की के बीच ऊर्जा संसाधनों पर कब्जे को लेकर पिछले कुछ समय से युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ऐसे हालात तब भी पैदा हुए थे जब पिछले साल ग्रीस ने एक छोटे मगर रणनीतिक रूप से बेहत अहम द्वीप कास्टेलोरिजो में अतिरिक्त सैन्य बल भेज दिया था। वर्ष 1982 के 'यूनाइटेड नेशंस कन्वेशन ऑन द लॉ ऑफ द सी' के हिसाब से ग्रीस को दोनों देशों के बीच के और विवादित द्वीप साइप्रस के आपसांस भूमध्यसागर में ज्यादा हिस्सा मिलता है। तुर्की इस बात को भी नहीं मानता। पूर्वी भूमध्यसागर में तुर्की का एक अहम रुख पूर्वी भूमध्यसागरीय गैस फोरम से इसे बाहर रखे जाने को लेकर है। इस फोरम का गठन जनवरी 2019 में कायरो में हुआ था और इसे 'भूमध्यसागरीय गैस के ओपेक' की संज्ञा दी गई थी। इस फोरम में ईजिप्ट, ग्रीस, साइप्रस, इजरायल,

गैरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली.... १

से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172

प्रदेश में 25 व 26 को चलेगा वैक्सीनेशन महाअभियान

सीएम ने अभियान को सफल बनाने मंत्री और कलेक्टरों से की वर्चुअली चर्चा

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में आगस्त 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने के लिए मर्मांगन की उपस्थिति में सभी कलेक्टर्स और क्राइसिस मैनेजर्से गुप्त के सदस्यों से वर्चुअल चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जन-प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों से मुख्यमंत्री राजकर विस्तृत निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सभी मिलकर इस महाअभियान को कामयाब बनाए। प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए तैयार की गई रणनीति के अनुसार 25 अगस्त को 20 लाख लोगों को पलटा और दूसरा डोज, 26 अगस्त को 10 लाख लोगों को राजकर प्राथमिकता से देने का नियन लिया गया है। अगस्त में भरत सरकार से प्राप्त करीब 74.7 लाख डोज में से 73.9 लाख की खपत हो चुकी है। प्रदेश में महाअभियान के लिए आवश्यक डोजज की व्यवस्था की गई है। प्रदेश की



वैक्सीनेशन के लिए पात्र पांच करोड़ 48 लाख 90 डजार आबादी में से तीन करोड़ 32 लाख को प्रथम डोज और 64 लाख 90 हजार आबादी को द्वितीय डोज लग चुका है। देश में मप्र, गुजरात के बाद सर्वाधिक वैक्सीनेशन करने वाला प्रांत है।

उत्तर का वातावरण बनाएं

सीएम श्री चौहान ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए सबको प्रेरित करें, ये पुण्य का कार्य है। वैक्सीनेशन महाअभियान में आशा और उमा, अंगमनाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी ही नहीं अन्य

विभाग भी सक्रिय भूमिका निभायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभारी मंत्री इस महाअभियान की तैयारियों पर जरुर स्वीकृत हैं। उत्तर का वातावरण बनाएं। नागरिक प्रथम डोज लगवाने के बाद लापरवाही बरत रहे हैं। दूसरा डोज न लगवाने से प्रथम डोज का प्रबल काम हो जाता है।

यह बात आजमन को बताते हुए जन-जग्यारण का कार्य आवश्यक है। सिवायक मह तक प्रथम डोज शत-प्रतिशत पात्र आबादी को लग जाए, यह लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जन-प्रतिनिधि सहयोग करें तो अभियान निश्चय ही सफल होगा। आम जनता भी इस महाअभियान से जुड़े हों। इसे सफल बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन पर टीका लगवाकर बात भाई-बहन याद रखें। रक्षाबंधन पर भाई-बहन इसर यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने टीका लगवाकर परसर यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने टीका लगवाकर जीवन रक्षा की कोशिश की गई है। या नहीं।

प्रथम महाअभियान में इंदौर अबल

प्रदेश में 21 जून से 3 जुलाई के मध्य संसालित प्रथम वैक्सीनेशन महाअभियान में सर्वाधिक प्रशंसन तीन जिले इंदौर, सीहोर और उज्जैन का रहा है। इंदौर जिले में 21.3 प्रतिशत, सीहोर जिले में 18.2 प्रतिशत और उज्जैन जिले में 16.5 प्रतिशत पात्र आबादी को प्रथम डोज लगाया जा रहा है। इंदौर जिले में प्रथम डोज 84 प्रतिशत लोग वैक्सीनेशन के लिए आये हैं। शरीरी क्षेत्र में वैक्सीनेशन कार्य अच्छा हुआ है। भोपाल शहर में प्रथम डोज 85 प्रतिशत और दूसरा डोज 25 प्रतिशत लोग जग्या चुके हैं।

मप्र का मार्डल सराहा गया : शर्मा

सासर विणु दत शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में कोविड के संकर को रोका है। जनता की भावी दरी से यह कार्य आसान हुआ। मप्र के मॉल की राशीय रसर पर सरहना हुआ है। जहाँ 25 अगस्त को वैक्सीन प्रयोग और द्वितीय डोज और 26 अगस्त को वैक्सीन के दूसरे डोज पर फोकस किया जा रहा है। समाजसेवी और कार्यकर्ता पात्र लोगों को वैक्सीनेशन केंद्रों तक लाने के साथ ही उनका सहयोग भी करें।



जोनवार दर्ज कर कॉल सेंटर की शिकायतों का करें निराकरण : तोमर

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बिजली विभाग से संबंधित कॉल सेंटर में सतना जिले की शिकायतों की लंबी संख्या अन्य जिले की तुलना में ज्यादा है। उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि जोनवार कॉल सेंटर की विभागीय योजनाओं की समीक्षा करें।

ऊर्जा मंत्री ने सतना में की विभागीय योजनाओं की समीक्षा

भोपाल इंदौर रहे। ट्रांसफार्मरों को अधिक सुचारा हो। ट्रांसफार्मरों के समीक्षा करें। ताकि वे लोड पाकर जलें नहीं।

ऊर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि कॉल सेंटर में अप्री भी 25 जुलाई से 20 अगस्त तक की अवधि में सतना जिले की 135 शिकायतें लंबित दिख रही हैं। कॉल सेंटर की विभागीय योजनाओं का जोनवार

रजिस्टर में दर्ज कर प्रत्येक शिकायत का निराकरण करायें। इसके लिये साधारण यंत्रों को नियमित रखें। ऊर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि तीन महीने बाद पुनः सतना आकर एक-एक विभागीय गतिविधि की समीक्षा स्वयं करें। तब तक जो कीमियां हों, उनका संधार कर लाएं।

उन्होंने विभाग की सुनिश्चित करायें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि विभाग की स्थिति वी समीक्षा वरिष्ठ अधिकारी निरंतर करें। श्री तोमर ने जिले में नियमित लाइनमैन, संविदा कॉल सेंटर की विभागीय योजनाओं के जोनवार की तुलना में ज्यादा हो। उन्होंने विभाग के लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइनमैन को जोनवार की तुलना में ज्यादा करें।

उर्जा मंत्री भी तोमर ने कहा कि लाइन

कैटरीना कैफ

Vicky Kaushal की
सगाई का क्या है सच?
सटीक खबर आई सामने

बॉलीवुड का पसंदीदा कपल कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विकी कौशल (Vicky Kaushal) की सगाई की खबरों ने बीते दिन फैंस को हैरान कर दिया था। फैंस सोच में पड़ गए थे कि बिना किसी आधिकारिक ऐलान के ऐसा कैसे हो गया। सोशल मीडिया पर लोग कैटरीना कैफ और विकी कौशल को बधाई देने लगे थे, लेकिन अब कैटरीना कैफ ने फैंस के सामने इन अफवाहों का सच खोल कर दिया है, जिसके बाद से फैंस का एक्साइटमेंट लेवल भी थोड़ा कम हो गया है।

नहीं हुई है सगाई

कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विकी कौशल (Vicky Kaushal) ने सगाई नहीं की है। कैटरीना कैफ ने आधिकारिक तौर पर इन खबरों को खारिज किया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस तरह की सारी खबरें झूठ हैं। साथ ही उन्होंने शादी और सगाई की कोई औपचारिक घोषणा भी नहीं की है। वहीं विकी कौशल की ओर से अभी कोई बयान सामने नहीं आया है, फिलहाल, अब ये साफ हो गया है कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल की सगाई नहीं हुई है।

पहले भी की बार आई हैं खबरें

बता दें, कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विकी कौशल (Vicky Kaushal) की शादी की खबरें अक्सर आती रहती हैं। बीते महीने भी शादी की तैयारियों की खबरें थीं, जिसे भी अफवाह कर दिया गया था। लंबे समय से दोनों की डेटिंग की खबरें हैं। दोनों ने इस पर कभी बात नहीं की, हमेशा ही बचते नज़र आए। विकी कौशल और कैटरीना साथ में अक्सर स्पॉट किए जाते हैं। कई बार कैटरीना के घर के बाहर विकी को स्पॉट किया गया। वहीं कुछ इवेंट पर भी दोनों साथ स्पॉट हुए। साथ ही कई सेलिब्रेशन भी दोनों ने साथ में किए हैं।

दोनों के पास कई फिल्में हैं लाइन्ड अप

वर्कफ्रंट की बात करें तो कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) इन दिनों कई फिल्मों की तैयारियों में व्यस्त हैं, जो जल्द ही अक्षय कुमार के साथ सुर्यवंशी में नजर आएंगी। वहीं फोन भूत में कैटरीना मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं। इसके लिए उनके साथ सिद्धांत चतुर्वेदी और इशान खट्टर लीड रोल में हैं। इसके अलावा वो सलमान खान के साथ टाइगर 3 की शूटिंग कर रही हैं। वहीं विकी कौशल भी कई फिल्मों में नजर आएंगी। दोनों को भी साथ स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस बेकरार हैं।



कैटरीना कैफ की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खबरें

बता दें, जो दोनों की बार आई हैं खब

